Scholars World
INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFEREED MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY REASERCH
Impact Factor: 4.433
Online ISSN: 2320-3145, Print ISSN: 2319-5789

# उच्च शिक्षा और शाश्वत विकास: एक राष्ट्रीय प्रगति

**प्रा.डॉ.वाल्मिक दशरथ सूर्यवंशी**

हिंदी विभाग, महाराजा सयाजीराव गायकवाड कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय मालेगांव कैंप, जि-नासिक महाराष्ट्रा

**सारांश :-**

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में समय के साथ अनेक परिवर्तनों और सुधारों से गुजरी है। आज यह प्रणाली विभिन्न विषयों, शोध, नवाचार और डिजिटल शिक्षा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार लागू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया है जिसमें बहुविषयक शिक्षा, शोध को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा, स्वायत्तता और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

**शिक्षा का अर्थ:-**

शिक्षा का वास्तविक अर्थ है सर्वांगीण विकास। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक तथा सामंजस्य पूर्ण विकास संभव है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के द्वारा शिक्षा ही व्यक्ति को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ बनाती है। साथ ही उसके आचारविचार-व्यवहार तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन की प्रेरणा प्रदान करती है।शिक्षित एवं उत्तर दायित्व के निर्वहन में अग्रणी नागरिक ही एक विकसित एवं सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्र का विकास प्रमुखतया समाज में शिक्षा की प्रकृति पर निर्भर करता है। राष्ट्र निर्माण में जहां प्राथमिक शिक्षा एक आधार के रूप में कार्य करती है तो वहीं उच्च शिक्षा तीक्ष्णता एवं कुशलता प्रदान करती है। विशेष रूप से प्रशिक्षित, विभिन्न विधाओं में पारंगत, ज्ञानी तथा कुशल नागरिकों के निर्माण द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं |

**बीज शब्द:-** उच्च शिक्षा, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा आदि।

**प्रस्तावना:-**भारत के अनेक विश्वविद्यालय आज **"**डिग्री उत्पादन केंद्र**"** के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहाँ व्यावहारिक कौशल अर्जन की तुलना में सैद्धांतिक एवं पारंपरिक अधिगम को प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा कार्यबल तैयार हो रहा है जो प्रमाण-पत्रों से युक्त तो है, किंतु व्यावसायिक रूप से यह विसंगति "ऐसे स्नातकों को सृजित कर सही है जो रोज़गार हीनता की समस्या का सामना कर रहे हैं", जिसके कारण उद्योगों को या तो अत्यधिक प्रशिक्षण लागत वहन करनी पड़ती है अथवा उच्च युवा बेरोज़गारी के बावजूद पद रिक्त रखने पड़ते हैं। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया है जिसमें बहु विषयक शिक्षा, शोध को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा, स्वायत्तता और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। हालांकि, उच्च शिक्षा प्रणाली अभी भी वित्तीय संसाधनों की कमी, गुणवत्ता में असमानता और शिक्षण विधियों में सुधार की चुनौतियों का सामना कर रही है। यह शोध पत्र उच्च शिक्षा के विकास में आई प्रमुख नीतियों, उनके प्रभावों और आगे की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करता है।

**शोध विस्तार :-**

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप विषयगत संस्थानों बजाय बहुविषयक एवं अनुसंधान-केंद्रित विश्वविद्यालयों को महत्त्व दिया जा रहा है।यह परिवर्तन समस्या-समाधान क्षमता को सुदृढ़ करता है, विभिन्न विषयों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है |भारत उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत एवं एकल नियामक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत यु. जी. सी./ ऐ. आय. सी. टी . तथा एन . सी. टी. ई जैसे बहु-स्तरीय नियमों द्वारा की जा रही विखंडित निगरानी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहल NEP 2020 की भावना के अनुरूप है।इसमें विनियमन, प्रत्यायन तथा शैक्षणिक मानकों हेतु पृथक-पृथक ऊर्ध्वाधर संरचनाओं की परिकल्पना की गई है, जिससे पारदर्शिता तथा विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा मिलता है।वित्तपोषण से संबंधित कार्य सरकार के पास ही रहेंगे, जबकि चिकित्सा एवं विधि शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा गया है|उन्नत वित्तपोषण और राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से अनुसंधान की गुणवत्ता, अंतर-विषयक सहयोग तथा वैश्विक सहभागिता में सुधार हो रहा है।नई फेलोशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे IIT, IIS जैसे अग्रणी संस्थानों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को

डॉक्टोरल अनुसंधान की ओर आकर्षित किया जा सके| भारत को ज्ञान-उपभोगकर्त्ता से ज्ञान-निर्माता राष्ट्र में रूपांतरित करन है | डिजिटल प्रौद्योगिकियों को पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति एवं संस्थागत शासन में समाहित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य-उन्मुख कौशल प्रदान किये जा सकें।इससे अधिगम का वैयक्तिकरण, अनुसंधान उत्पादकता तथा उद्योग-समन्वय में वृद्धि हो रही है। शिक्षण एवं अनुसंधान में भाषाई समावेशन से पहुँच और प्रासंगिकता का विस्तार होता है। परंपरा और आधुनिकता का यह समन्वय भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है।शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से IKS में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं, जिनके लिये पाठ्यक्रम विकास तथा संकाय-प्रशिक्षण पहलें संचालित की जा रही हैं |ज्ञान एवं अनुसंधान तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण: "एक राष्ट्र, एक सदस्यता तक पहुचना है |शिक्षा के माध्यम से सरकार ने शोध पत्रिकाओं की सदस्यता को केंद्रीकृत कर दिया है, जिससे छोटे एवं राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की वित्तीय बाधाएँ दूर हो रही हैं।उच्च-स्तरीय वैश्विक अनुसंधान तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी कल्याण को अब शैक्षणिक सफलता तथा संस्थागत गुणवत्ता का अनिवार्य घटक माना जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में परामर्श, मार्गदर्शन तथा तनाव-प्रबंधन प्रणालियों को अकादमिक नियोजन का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य एवं मेंटरशिप ढाँचे को प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। उच्च शिक्षा प्रणाली में स्थायी शिक्षकों की गंभीर कमी विद्यमान है, जिसके चलते संस्थान अस्थायी (एड-हॉक) शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भर हो गये हैं। ऐसे शिक्षकों के पास न तो अनुसंधान हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन होता है और न ही रोज़गार-सुरक्षा, जिससे संस्थागत स्मृति, मार्गदर्शन व्यवस्था तथा शैक्षणिक निरंतरता प्रभावित होती है।यह स्थिति भारत के **"विश्वगुरु"** बनने के आकांक्षी लक्ष्य को भी बाधित करती है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप विषयगत संस्थानों बजाय बहुविषयक एवं अनुसंधान-केंद्रित विश्वविद्यालयों को महत्त्व दिया जा रहा है।यह परिवर्तन समस्या-समाधान क्षमता को सुदृढ़ करता है, विभिन्न विषयों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है |भारत उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकीकृत एवं एकल नियामक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत यु. जी. सी./ ऐ. आय. सी. टी . तथा एन . सी. टी. ई जैसे बहु-स्तरीय नियमों द्वारा की जा रही विखंडित निगरानी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहल NEP 2020 की भावना के अनुरूप है।इसमें विनियमन, प्रत्यायन तथा शैक्षणिक मानकों हेतु पृथक-पृथक ऊर्ध्वाधर संरचनाओं की परिकल्पना की गई है, जिससे पारदर्शिता तथा विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा मिलता है।वित्तपोषण से संबंधित कार्य सरकार के पास ही रहेंगे, जबकि चिकित्सा एवं विधि शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा गया है|उन्नत वित्तपोषण और राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से अनुसंधान की गुणवत्ता, अंतर-विषयक सहयोग तथा वैश्विक सहभागिता में सुधार हो रहा है।नई फेलोशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे IIT, IIS जैसे अग्रणी संस्थानों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को डॉक्टोरल अनुसंधान की ओर आकर्षित किया जा सके| भारत को ज्ञान-उपभोगकर्त्ता से ज्ञान-निर्माता राष्ट्र में रूपांतरित करन है | डिजिटल प्रौद्योगिकियों को पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति एवं संस्थागत शासन में समाहित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य-उन्मुख कौशल प्रदान किये जा सकें।इससे अधिगम का वैयक्तिकरण, अनुसंधान उत्पादकता तथा उद्योग-समन्वय में वृद्धि हो रही है। शिक्षण एवं अनुसंधान में भाषाई समावेशन से पहुँच और प्रासंगिकता का विस्तार होता है। परंपरा और आधुनिकता का यह समन्वय भारत के सभ्यतागत आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है।शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से IKS में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं, जिनके लिये पाठ्यक्रम विकास तथा संकाय-प्रशिक्षण पहलें संचालित की जा रही हैं |ज्ञान एवं अनुसंधान तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण: "एक राष्ट्र, एक सदस्यता तक पहुचना है |शिक्षा के माध्यम से सरकार ने शोध पत्रिकाओं की सदस्यता को केंद्रीकृत कर दिया है, जिससे छोटे एवं राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की वित्तीय बाधाएँ दूर हो रही हैं।उच्च-स्तरीय वैश्विक अनुसंधान तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी कल्याण को अब शैक्षणिक सफलता तथा संस्थागत गुणवत्ता का अनिवार्य घटक माना जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में परामर्श, मार्गदर्शन तथा तनाव-प्रबंधन प्रणालियों को अकादमिक नियोजन का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य एवं मेंटरशिप ढाँचे को प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। उच्च शिक्षा प्रणाली में स्थायी शिक्षकों की गंभीर कमी विद्यमान है, जिसके चलते संस्थान अस्थायी (एड-हॉक) शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भर हो गये हैं। ऐसे शिक्षकों के पास न तो अनुसंधान हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन होता है और न ही रोज़गार-सुरक्षा, जिससे संस्थागत स्मृति, मार्गदर्शन व्यवस्था तथा शैक्षणिक निरंतरता प्रभावित होती है।यह स्थिति भारत के **"विश्वगुरु"** बनने के आकांक्षी लक्ष्य को भी बाधित करती है। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के शैक्षिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना। संयुक्त राष्ट्र ने तर्क दिया कि मानव होने के लिए सीखना आवश्यक है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सतत विकास है। यह महसूस करते हुए कि शिक्षा न केवल सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, बल्कि मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का एक मौलिक और प्रभावी साधन भी है, संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में एक आयोग की स्थापना की ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि 21 वीं सदी में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। भारतीय शिक्षाविद् कर्ण सिंह फ्रांस के वित्त मंत्री जैक्स डेलोर की अध्यक्षता वाले 14 सदस्यीय आयोग के सदस्यों में से एक थे। "सतत विकास" शब्द पहली बार 1987 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग (ईईसीडी) द्वारा गढ़ा गया था। आयोग के अनुसार, सतत विकास अगली पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान पीढ़ी की क्षमता है। कुछ ने सतत विकास की व्याख्या 'सतत विकास' या 'सतत विकास' के रूप में भी की है; हालांकि, सतत विकास की अवधारणा को पहली बार 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जिसमें सतत विकास 'एक ऐसा विकास है जो वर्तमान के विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की विकास क्षमता से समझौता नहीं करता है। संक्षेप में, सतत विकास का अर्थ है कि अगली पीढ़ी को हमारे विकास के परिणाम के लिए भारी कीमत नहीं चुकानी पड़े, यह विकास के दौरान आवश्यक तत्वों को संरक्षित और संरक्षित करना है। विकास शब्द

का अर्थ और अर्थ जीवन शैली की प्रगति है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकृति जैसे कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शिक्षा भविष्य की दुनिया के साथ-साथ व्यक्तियों और समाज को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सतत विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस संबंध में, रियो डी जनेरियो में 1992 के सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा पर विचार किया गया। पहला, बुनियादी शिक्षा का उन्नयन और सुधार; दूसरा, सतत विकास के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन; तीसरा, सतत विकास के बारे में जनता के बीच जागरूकता और समझ का विकास, और चौथा, प्रशिक्षण। रियो डी जनेरियो में 2012 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लगभग 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और आधिकारिक तौर पर समर्थन किया गया था। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2016 से 2030 तक 15 साल का समय निर्धारित किया गया था। सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत कुल दस अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक सभी पुरुषों और महिलाओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो; रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना और समाज के प्रत्येक कमजोर व्यक्ति को सभी प्रकार की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

**शिक्षक की भूमिका**

चारित्रिक विकास तथा श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं की योग्यता को बढ़ाएं तथा राष्ट्रीय और वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप छात्र के व्यक्तित्व का निर्माण करें ताकि वह राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। शिक्षक की विशेषता बताते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं- श्लिष्टाक्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता। यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ श्रेष्ठ शिक्षक वही है जिन्हें विषय की गहरी समझ हो साथ ही जो अपने अर्जित ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ तरीके से छात्र तक संप्रेषित कर सके। उच्च शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य एक ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करना है जिसमें कि छात्र तर्कसंगत रूप से विचार करने तथा समालोचनात्मक रूप में उन्हें अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सके। उच्च शिक्षा की शिक्षण पद्धतियां शिक्षण पद्धति या विधि में शिक्षण आव्यूहों व युक्तियों दोनों का समावेश होता है जिसका अनुसरण कर अध्यापक अधिगम को रोचक, आसान व प्रभावपूर्ण बनाता है। विधि परिणाम की गुणवत्ता निर्धारित करती है। शिक्षण विधि के महत्व को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह विचार प्रकट किया सर्वोत्तम पाठ्यचर्या तथा परिपूर्ण पाठ्यक्रम भी तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि इसे शिक्षण की सही विधियों तथा सही प्रकार के अध्यापकों द्वारा जीवन्त ना किया जाए। तक कि इसे शिक्षण की सही विधियों तथा सही प्रकार के अध्यापकों द्वारा जीवन्त ना किया जाए।

वर्तमान में उच्च स्तर पर शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं- 1. ज्ञान प्रदान करना। 2. प्राप्त ज्ञान को प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। 3. सूचना एवं ज्ञान के परीक्षण की क्षमता विकसित करना। 4. नवीन ज्ञान निर्माण की योग्यता विकसित करना। 5. व्यक्तिगत विकास के अवसर देना। 6. स्वयं के अधिगम को नियोजित एवं व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है 1. समस्या समाधान विधि 2. आगमन विधि 3. निगमन विधि 4. व्याख्यान विधि 5. दत्त कार्य विधि 6. प्रोजेक्ट विधि 7. कार्यशाला विधि गुणात्मक उन्नयन हेतु उपयुक्त शिक्षण पद्धति- सूचना एवं संचार तकनीकी एवं वैश्वीकरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक गति प्रदान की है। अतः उच्च शिक्षा में गुणात्मक एवं वर्तमान समय की अपेक्षाओं के अनुरूप सुधार हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण हेतु उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। मुक्त अधिगम पद्धति, समूह कार्य पद्धति, एवं प्रोजेक्ट विधि इसमें सहायक सिद्ध हो सकती है। उच्च शिक्षा में मुक्त अधिगम विधि के अंतर्गत सरकार द्वारा SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) को प्रस्तुत किया गया है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित है। इसमें 2000 पाठ्यक्रमों, 80000 घंटों का अधिगम सम्मिलित हैं जो की स्नातक, स्नातकोत्तर, अभीयांत्रिकी तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। स्वयम् SWAYAM में वीडियो, ट्यूटोरियल्स, ई सामग्री, स्व मूल्यांकन व विचार विमर्श का समावेश किया गया है। इसी प्रकार SWAYAM PRABHA जो 32 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का एक समूह है वह UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS आदि के द्वारा तैयार विभिन्न पाठ्यक्रमों पर आधारित लिखित सूचना एवं सामग्री का प्रसारण करता है। इसी प्रकार सक्रिय अधिगम पद्धति जिसमें अधिगम का संपूर्ण उत्तरदायित्व छात्र पर होता है, तथा समस्या समाधान पद्धति जिसमें समस्या के संभावित समाधानों का अन्वेषण करते हुए छात्र अधिगम करता है भी अत्यधिक महत्व रखती है। उपर्युक्त शिक्षण पद्धतियां छात्र को ज्ञान के परीक्षण की क्षमता प्रदान करती है तथा अधिगम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। साथ ही छात्र को नवीन ज्ञान निर्माण में सक्षम बनाकर शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन करती है |

**निष्कर्ष :-**

भारत की उच्च शिक्षा यात्रा अब केवल विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समावेशन एवं उत्कृष्टता की भी माँग है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा जब विश्वविद्यालय स्वायत्त रूप से कार्य कर सकेंगे, निर्भीक नवाचार करेंगे तथा बड़े पैमाने पर रोजगारोन्मुख ज्ञान प्रदान

करेंगे। उच्च शिक्षा और शाश्वत विकास नीति ने उच्च शिक्षा तक पहुँच का विस्तार किया है, तथापि यह संस्थागत गुणवत्ता एवं अनुसंधान क्षमता से संबंधित चुनौतियों का पूर्णतः समाधान नहीं कर पाई है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में द्वितीय-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कर के उसमे विकास की दिशा तय करनी होगी। द्वितीय-पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मात्र डिग्री प्रदान करने वाले केंद्रों से बदलकर अनुसंधान, कौशल एवं सामाजिक गतिशीलता के सशक्त इंजन बनाना होना चाहिये। तभी भारत अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश को दीर्घकालिक विकासात्मक लाभ में रूपांतरित कर सकेगा।उच्चतर शिक्षा के कुछ क्षेत्रों से जैसे प्रवेश की अनुमति देना विद्यार्थियों की संख्या और पाठ्यक्रमों को शुरू करने के संबंध में संचालन निर्णय लेने के अनुमति अभिशासन और प्रबंधन तथा विद्यार्थी अधिगम स्तर से संबंधित मुद्दों की समग्र निष्पादन की मॉनिटरिंग में विनियमन की आवश्यकता होती है साथी सार्वजनिक और निजी संस्थानों में और अधिक पारदर्शिता अपेक्षित है। भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को सही मायने में बदलने के लिये, सुधारों को विस्तार से आगे बढ़कर गुणवत्ता, समावेशिता और प्रासंगिकता पर केंद्रित होना चाहिये। जैसा कि कोठारी आयोग ने उचित ही बल दिया था, "शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम होना चाहिये।" कुशल संकाय, उत्कृष्ट शोध, उद्योग संबंधों और एथिकलशिक्षा के के माध्यम से इस दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने से यह सुनिश्चित होगा कि उच्च शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का वाहक बने।

**संदर्भ सूची:-**

1.उच्च शिक्षा दशा एवं दिशा -श्री अतुल कोठारी -पुष्प-62
2. शाश्वत विकास की अवधारणा-डॉ.अमर कुमार - सामयिक बुक्स नई दिल्ली
3.राष्ट्रीय शिक्षा नीति- मानव संसाधन विकास मंत्रालय -बारत सरकार
4. .उच्च शिक्षा शोध वर्त्तमान संदर्भा में -डॉ,मोहन बैरागी
5.भारतीय उच्च शिक्षा :भविष्य की कल्पना -पवन अग्रवाल
6. उच्च शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का महत्व -डॉ.ज्योति सिंह
7. उच्च शिक्षा का भविष्य -युग चटर्जी ।
8. उच्च शिक्षाप्रणाली :मुख्य आवधारानाएँ -गंगादत्त राय।

---